

कॉमरेड कन्हैया, उमर और अनिर्बान को रिहा करो!

राजद्रोह व अन्य फर्जी आरोपों को रद्द करो!

जेएनयू के आठ छात्रों का निलंबन वापस लो! आईपीसी से राष्ट्रद्रोह को रद्द करो!

'रोहित एक्ट' को लागू करो! विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिवादी उत्पीड़न बंद करो!

स्मृति ईरानी इस्तीफा दो! सत्ता का दुरुपयोग बंद करो! झूठ बोलना बंद करो!

वे हमारे गीत क्यों रोकना चाहते हैं परचा पोस्टर पर पाबंदी नहीं सहेंगे!

जेएनयू में उपलब्ध लोकतांत्रिक बहुलता के अवकाश को सीमित करने की मंशा को आगे बढ़ाते हुए समूची स्टेट व यूनिवर्सिटी मशीनरी ने सारी हदों को पार करते हुए अब पोस्टर व पैंफलेट छापने को रोकना शुरू कर दिया है. इसी के तहत जेएनयू के अंदर व बाहर फोटोकॉपी करनेवाले दुकानदारों को छात्रों के पोस्टर-पैंफलेट न छापने के निर्देश दिए गए हैं! खबर है कि कुछ दुकानदारों से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है और सख्ती बरतने का संकेत किया है.

सत्ता का दुरुपयोग करके लोकतांत्रिक स्वयं को दबाने की इस कोशिश की हम निंदा करते हैं. भाजपा सरकार और समूचे राज्य-तंत्र की मंशा यह है कि उनके सिवाय अन्य किसी भी स्वर को सार्वजनिक न होने दिया जाए - इसके लिए वे किसी भी हद तक उतरने को उतारू हैं. वे चाहते हैं कि जेएनयू में डिबेट, डिस्कसन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुंद किया जाए. हमारे पैंफलेट्स में सत्ताधारी वर्ग की नीतियों और राजनीति की व्यवस्थित आलोचना पेश की जाती है - यही हमारा 'अपराध' है और इसीलिए इसे रोकने की जरूरत समझी जा रही है. गिरफ्तार करके, थाने में दिन दिनभर पूछताछ करके, राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाकर वे हम लोगों को डराना चाहते हैं. मगर साथियों! स्टेट मशीनरी के उपरोक्त तमाम षड्यंत्र अब तक सफल नहीं हो सके हैं और पूरी दुनिया के सामने, हर मौके पर उनको मुंह की खानी पड़ी है. यह तय है कि हम चुप नहीं रह सकते. हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता. हमारे पोस्टरों को छपने से रोका नहीं जा सकता.

मगत सिंह इस बार न लेना काया भारतवासी की
देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की
यदि जनता की बात करोगे, तुम गद्दार कहाओगे,

बम्म-सम्ब की छोड़ो . भाषण दोगे, पकड़ें जाओगे! - शैलेन्द्र

मोदी सरकार ने असहमति के अधिकार और कैंपसों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है. एक नौजवान . रोहित वेमुला . की जान इस युद्ध की भेंट चढ़ गई तो कई और नौजवान छात्र ऐसे हैं जिन पर राजद्रोह के मामले डालकर उन पर कीचड़ उछाला जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और हिरासत में उन पर हमले किये जा रहे हैं. जेएनयू कैंपस में 9 फरवरी के आयोजन में जो नारे लगे, उनकी जेएनयू छात्रसंघ समेत सभी प्रगतिशील व लोकतांत्रिक संगठनों ने निंदा की है. हालांकि अब यह स्पष्ट हो चुका है कि कथित नारेबाजी मोदी सरकार के लिए जेएनयू पर चौतरफा हमला करने का एक बहाना मात्र है - जेएनयू पर हमले का असल मकसद छात्र आंदोलन की उस आवाज को कुचलना है जो उच्च शिक्षा में फंड-कट व भाजपा सरकार की छात्र विरोधी व जनविरोधी नीतियों के विरोध में लगातार उग्र होती जा रही है.

लेकिन दिल्ली की सड़कों पर . मुख्यतः छात्रों और नौजवानों की . दो ऐतिहासिक गोलबंदियों ने कैंपसों पर मोदी के हमलों को करारा जवाब दिया है.

18 फरवरी को, 'देशद्रोही JNU' के खिलाफ टीवी चैनलों द्वारा तैयार किये जा रहे माहौल को धता बताते हुए, दिल्ली के हजारों छात्र नौजवान, मेहनतकश महिला और पुरुष, बुद्धिजीवी और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े नागरिक JNU के पक्ष में सड़कों पर उतर आये. उन्होंने JNU छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की तत्काल रिहाई, छात्रों के खिलाफ राजद्रोह के सभी मामलों को वापस लेने और JNU के आठ छात्र कार्यकर्ताओं के मनमाने ढंग से किये गए निलंबन को वापस लेने की मांग की. उन्होंने राजद्रोह के कानून को इंडियन पीनल कोड (आईपीसी) से हटाने की मांग की. सबसे ज्यादा, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सच्ची देशभक्ति का मतलब है अपनी असहमति को डटकर कहना, जनता के अधिकारों का सम्मान करना और सत्ता को सत्य सुनाने का साहस रखना.

23 फरवरी को, ज्वाइंट एक्शन कमिटी फॉर जस्टिस फॉर रोहित वेमुला के 'चलो दिल्ली' के आह्वान पर देश भर से छात्र दिल्ली पहुंचे. दिल्ली की सड़कों पर मार्च करने वाले हजारों लोगों ने कहा कि वे मोदी सरकार को दलित छात्र और कार्यकर्ता की मौत की जिम्मेदारी से हाथ नहीं खींचेंगे.

रोहित वेमुला और JNU छात्रों का उत्पीड़न

एक ABVP नेता के बनावटी चोटों को आधार बनाकर रोहित को उसके विश्वविद्यालय से बर्खास्त कर दिया गया था. याकूब मेमन की फांसी के खिलाफ आयोजित एक कार्यक्रम में रोहित और उसके साथियों द्वारा दिए गए नारों के आधार पर उसे देशद्रोही करार दिया गया था. आठ छात्र जिनमें JNUSU अध्यक्ष कन्हैया कुमार, JNUSU महासचिव रामा नागा, पिछले JNUSU अध्यक्ष आशुतोष कुमार और पिछले JNUSU उपाध्यक्ष अनंत प्रकाश नारायण और उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्या शामिल हैं, को विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया और उनपर राजद्रोह के मुकदमे झूठे वीडियो, झूठे द्वाइस और झूठे खुफिया रिपोर्ट्स के आधार पर दायर किये गए. रोहित और JNU स्टूडेंट्स पर कीचड़ उछालने और उनके निलंबन की शुरुआत ABVP ने की और

भाजपा के सांसदों ने इन्हें आगे बढ़ाया. रोहित वेमुला के उत्पीड़न के दुखद अंत से सीख लेने के बजाय, मोदी सरकार ने JNU पर निशानेबाजी करके छात्रों पर हमले को सिर्फ जारी ही नहीं रखा बल्कि ज्यादा बड़े पैमाने पर चलाया.

मोदी सरकार रोहित और JNU से डरती क्यों है?

रोहित और JNU के छात्र भारत के ग्रामीण इलाकों के साधारण घरों से आने के बावजूद विश्वविद्यालयों में पहुँचते हैं, पढ़ते हैं, विश्वविद्यालयों को पिछड़े और वंचित तबकों से आने वाले छात्रों की पहुँच के भीतर लाते हैं और हाशिये पर खड़े लोगों की आवाज़ उठाते हैं. उन्होंने उच्च शिक्षा पर कॉरपोरेट वर्चस्व, फेलोशिप में कटौती और देश की उच्च शिक्षा को विश्व व्यापार संगठन WTO के हाथों दे देने के विरोध में आंदोलनों का नेतृत्व किया. भाजपा और RSS ने JNU को दी जाने वाली सब्सिडी का उल्लेख करते हुए पूछा कि JNU के छात्र सरकार के खिलाफ आवाज़ क्यों उठाते हैं जबकि सरकार उन्हें सब्सिडी देती है. हम उनसे कहना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय मजदूर और किसानों की मेहनत के पैसों से चलते हैं, इसलिए हम उनके पक्ष में आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे.

भारत की बर्बादी और टुकड़े कौन करना चाहता है?

जब केंद्रीय सरकार के मंत्री भारतीयों को 'रामजादों' व 'हरामजादों' में, और गोमांस खानेवालों तथा न खाने वालों में बाँटते हैं, जब वे अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाहों का विरोध करते हैं, जब वे दलित नरसंहार के पीड़ितों को 'कुत्ते' कहते हैं, तो क्या वे भारत के टुकड़े नहीं करते? जब RSS समर्थक अपनी सोच के कारण लोगों को मारते हैं, जिसमें गाँधी से लेकर दाभोलकर से लेकर कलबुर्गी तक शामिल हैं, तब क्या वे भारत को बर्बाद नहीं कर रहे होते? हम कहेंगे कि ऐसी शक्तियों का विरोध करके छात्र देश की एकता की रक्षा कर रहे होते हैं.

बीजेपी के समर्थकों में एक प्रमुख चेहरा, अभिनेता अनुपम खेर ने HCU से लेकर JNU तक कैम्पसों के भीतर होने वाले दमन को 'पेस्ट कण्ट्रोल' कहा है, और भाजपा तथा ABVP के नेताओं ने कहा है कि कैम्पसों को वामपंथियों और प्रगतिशील कार्यकर्ताओं से मुक्त करने और शुद्धिकरण की जरूरत है. क्या रोहित कोई कीड़ा था जिसे HCU से निकालकर कैम्पस का शुद्धिकरण किया गया? ऐसी अमानवीय भाषा और भाजपा नेताओं द्वारा दलित और मुस्लिम पीड़ितों की तुलना कुत्तों और पिल्लों से करना हिटलर के वक्त की जर्मनी की याद दिलाता है.

जब सरकार किसानों और आदिवासियों से ज़मीन और संसाधन छीनकर उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले करती है, जब वे मजदूरों पर दमन करते हैं, जब वे उच्च शिक्षा को WTO के हाथों बेचते हैं, तो क्या वे देश को बर्बाद नहीं करते हैं? वे, JNU के छात्र, देशभर के छात्र-नौजवान और जन आन्दोलन ही हैं जो कि सही मायने में देशभक्त हैं, भारत के लोगों को बर्बादी से बचा रहे हैं.

रोहित वेमुला और JNU के पक्ष में उभरे छात्र और नौजवानों के आंदोलनों ने बड़ी कामयाबी से संघ के 'राष्ट्रवाद' के आवरण को उतार फेंका है और संवैधानिक आज़ादी पर दमन, हिन्दुत्ववादी शक्तियों और कॉर्पोरेट परस्त नीतियों के विरोध में उठ रहे स्वरो को दबाने की कोशिशों के सरकारी एजेंडे का पर्दाफाश किया है, जिसमें संघी गुंडों और पुलिस तंत्र का इस्तेमाल करके जानलेवा हमले करवाना शामिल है.

अम्बेडकर के विचारों और संविधान पर हमले

छात्रों के इस आन्दोलन ने नकली वीडियो और अन्य नकली सामग्री का इस्तेमाल करके JNU के खिलाफ नफ़रत फैलाने की कोशिश करने वाले कुछ मीडिया चैनलों का भी भंडाफोड़ किया है. इस शर्मनाक हरकत के बरक्स कुछ अन्य हिम्मती पत्रकार भी हैं, जिनमें एक नौजवान पत्रकार शामिल है, जिन्होंने ऐसे ही एक चैनल से इस्तीफ़ा देकर नकली वीडियो द्वारा JNU और वामपंथियों के खिलाफ माहौल तैयार करने की कोशिशों का पर्दाफाश भी किया है.

JNU के खिलाफ नफ़रत फैलाने की संघी कोशिश करने वाले कहते हैं, 'जो अफज़ल की बात करेगा, वो अफज़ल की मौत मरेगा!'. जबकि जम्मू-कश्मीर में भाजपा एक बार फिर PDP के साथ सरकार बनाने की तैयारी में है, जो कि अफज़ल की फाँसी को 'न्याय का स्वांग' कहती है और अफज़ल के अवशेषों को कश्मीर ले जाना चाहती है.

पर ये बात अब छुपी नहीं है कि 'अफज़ल की बात' सिर्फ एक बहाना है. 'अम्बेडकर की बात' को भी नफ़रत और हिंसा का सामना करना पड़ता है. हाल ही में, भाजपा के युवा संगठन, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ग्वालियर में JNU के प्रोफ़ेसर विवेक कुमार पर लाठियों और गोलिएं से तब हमले किये जब वे एक आमसभा में 'बाबा साहेब के सपनों का भारतीय समाज' पर बोलने जा रहे थे. भाजपुमो ने संविधान और डा. अम्बेडकर की अन्य किताबों की प्रतियों को बर्बाद भी किया.

भाजपा, RSS और ABVP अम्बेडकर और संविधान के प्रति अपनी नफ़रत और घृणा को छुपा नहीं पा रहे. 'वकीलों' और एक भाजपा विधायक द्वारा न्यायालय परिसर के भीतर छात्रों, शिक्षकों और पत्रकारों को बेधड़क पिटवाकर मोदी सरकार, संविधान की अवमानना का सन्देश ही तो दे रही है!

मानव संसाधन-विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा आयोजित कुलपतियों की बैठक में कैम्पसों में दलित आत्महत्याओं के ज्वलंत मुद्दे और धोराट कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें कैम्पसों में जातिगत भेदभाव को ख़त्म करने वाले 'रोहित एक्ट' के सुझाव पर चुप्पी बनी रही. स्कॉलरशिप ख़त्म करने और भारत की उच्च शिक्षा पर WTO के कायदे थोपने की कोशिशों पर भी चुप्पी बनी रही. बल्कि मंत्री महोदया ने शर्मनाक ढंग से सभी कैम्पसों में तिरंगा लगाने के आदेश के पीछे इन मुद्दों को दबाने की कोशिश की, जबकि ज्यादातर कैम्पसों में तिरंगा पहले से ही लगा हुआ है.

संघ परिवार और मोदी सरकार - जो अंगरेजों से माफ़ी मांगने वाले वीर सावरकर और गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के प्रशंसक पूजक हैं - हमेशा से अम्बेडकर और भगत सिंह की विरासत से डरते रहे हैं. अब वे अम्बेडकर और भगत सिंह के अनुयायियों को 'देशद्रोही' साबित करने में जी जान से जुटे हैं. वे हम कोशिश में कामयाब नहीं हो सकते. अम्बेडकर व भगत सिंह को बहादुर युवा अनुगामी उन्हें करारा जवाब देंगे और संघी हमलों से लोकतंत्र को बचायेंगे. असहमति के अपराधीकरण के विरोध में, संविधान लोकतंत्र और कैम्पस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जेएनयूसयू ने बुधवार 2 मार्च को पार्लियामेंट मार्च की कॉल दी है! इंटरनेशनल प्रोटेस्ट डे के इस मौके पर छात्रों नौजवानों का कारवां मंडी हाउस से पार्लियामेंट के लिए 2 बजे रवाना होगा! मंगल डाक पर 12 बजे एकत्र हों!